



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]
No. 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 20, 1985/ चैत्र 30, 1907
NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 20, 1985/CHAITRA 30, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

भाग II--खण्ड IV PART II--Section IV

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 1985

का. नि. आ 67--राष्ट्रपति, सचिवालय के अनुच्छेद 309 के
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, साधारण भविष्य निधि
(रक्षा सेवा) नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्न
लिखित नियम बनाने हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम साधारण भविष्य निधि
(रक्षा सेवा) तीसरा संशोधन नियम, 1984 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. साधारण भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम, 1960 में, नियम
11 के उपनियम (4) के नीचे "टिप्पण" के स्थान पर निम्नलिखित
टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :-

"टिप्पण :- 6 मास और 1 वर्ष का कालावधि से परे निधि अति-
शेष पर ब्याज का सदाय :-

(1) रक्षा लेखा विभाग कार्मिक एक वर्ष तक--सर्वोच्च नियंत्रक,
लेखा (निधि), मेरठ

सेना सिविलियन

किसी भी कालावधि तक -- नियंत्रक
रक्षा लेखा (ओ. आर. एम.)
उत्तरी मेरठ

(2) सिविलियन, वायुसेना

किसी भी कालावधि तक--समा-
वेशक आफिसर, वायुसेना केन्द्रीय
लेखा कार्यालय, नई दिल्ली

(3) नौसेना में सिविलियन

किसी भी कालावधि तक --नियं-
त्रक, रक्षा लेखा, (नौसेना)
मुम्बई।

(4) औद्योगिक और अनीसोमिक
कर्मचारी कारखाना

किसी भी कालावधि तक -- नियंत्रक
लेखा (एक वाई. एम)
कलकत्ता

(5) साधारण आश्रित इंजिनियरिंग
बल सिविलियन कार्मिक

किसी भी कालावधि तक -- नियंत्रक
रक्षा लेखा, (दक्षिणी कमान)
पुणे।

(6) नौसेना मुख्यालय और सेना
मुख्यालय तथा अंतर सेवा संग-
ठनों में सेवा करने वाले
सिविलियन

किसी भी कालावधि तक -- नियंत्रक,
रक्षा लेखा (मुख्यालय), नई
दिल्ली।

द्वारा व्यक्तिगत रूप से अपना यह समाधान करने के
पश्चात् प्राधिकृत किया जाएगा कि सदाय में विशेष ऐसा परिस्थि-
तियों के कारण हुआ है जो अधिकता के या उस व्यक्ति के जिसे
ऐसा संभाव्य किया जाना है, नियंत्रण में बाहर था, और ऐसे प्रत्येक मामले

में उस विषय में हुए प्रशासनिक बिलंब का पूर्ण रूप से अन्वेषण किया जाएगा और यदि कोई कार्रवाई अपेक्षित हो तो वह की जाएगी।”

[मामला सं. 19 (6)/79/डा. (मिबि.-2)]

[रक्षा (वित्त) यू. प्रो. सं. 1943 फं. ए. 1984]

रामकृष्ण, उप सचिव

टिप्पण :- मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 तारीख 27-10-1961 में पृष्ठ 63 पर, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का. नि. आ. 331 तारीख 27-10-1961 द्वारा प्रकाशित किए गए और बाद में उनका रक्षा मंत्रालय का. नि. आ -- 170/1980 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 20th February, 1985

S.R.O. 67.—In exercise of the powers conferred by the Proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the General Provident Fund (Defence Services), Rules, 1960, namely :—

1. (1) These rules may be called the General Provident Fund (Defence Services) First Amendment Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the General Provident Fund (Defence Services) Rules, 1960 for the “Note” under sub-rule (4) of rule 11 the following Note shall be substituted, namely :—

“Note.—Payment of interest on the fund balances beyond a period of 6 months and beyond 1 year may be authorised by :—

(i) Defence Accounts Department personnel	upto one year	Joint Controller of Defence Accounts Funds, Meerut.
Army civilians	upto any period	The Controller of Defence Accounts (ORs) North, Meerut.

(ii) Civilians of Air Force	upto any period	The Officer Commanding Air Force Central Accounts Office New Delhi.
(iii) Civilians in Navy	upto any period	The Controller of Defence Accounts, (Navy) Bombay.
(iv) Industrial and Non-Industrial employees of factories.	upto any period	The Controller of Defence Accounts (Fys), Calcutta.
(v) General Reserve Engineering Force and Army Headquarters Civilians personnel.	upto any period	The Controller of Defence Accounts, Southern Command, Pune.
(vi) Civilians serving in Naval Headquarters and Army Headquarters and Inter-Services Organisations.	upto any period	The Controller of Defence Accounts (Headquarters); New Delhi.

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken.”

[Case No. 19(6)/79/D (Civ-II)
Defence (Fin.) u.o. No. 1983-DA of 1984.]
RAMA KRISHNA, Dy. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section IV, dated 27th October, 1961 Page 63, vide Government of India, Ministry of Defence SRO No. 331, dated 27th October, 1961 and was subsequently amended by Ministry of Defence SRO No. 170 of 1980.

CORRIGENDUM

New Delhi, the 1st April, 1985

S.R.O. 68.—In the Army (Amendment) Rules, 1985 published with the notification of the Government of India, Ministry of Defence, No. S.R.O. 55, in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 9th March, 1985, at page 97. in column 1, in line 20, after the word “trial”, for the word “or”, read the word “of”.

[File No. 4(2)/884/D (AG)]
V. M. LABROO, Dy. Secy. (AG)